

कुल संख्या कितनी है और उनके वेतनमान क्या क्या हैं;

(ख) उनमें से हिन्दी तथा अंग्रेजी के संवाददाता कितने-कितने हैं और दोनों प्रकार के संवाददाताओं के वेतनमान क्या-क्या हैं;

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी भाषी लोगों की संख्या के अनुपात में तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं की संबंधानिक स्थिति को देखते हुए क्या अंग्रेजी तथा हिन्दी के संवाददाताओं का अनुपात 1:10 रखने का है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या अंग्रेजी संवाददाताओं को इस आशय के अनुदेश जारी करने का विचार है कि वे समाचार अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में भेजें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT—328/69]

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

(घ) ऐसे अनुदेश सम्भव नहीं हैं तथापि संवाददाता समाचार अंग्रेजी या हिन्दी में भेज सकते हैं परन्तु दोनों भाषाओं में नहीं, क्योंकि इससे प्रतिरिक्त खर्च होगा। अंग्रेजी के कई संवाददाता जो हिन्दी जानते हैं अपने कुछ समाचारों को हिन्दी में भी भेजते हैं।

आकाशवाणी में ठेका प्रणाली समाप्त करना

2877. श्री रणजीत सिंह :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री सूरज मान :

श्री वृज भूषण लाल :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री रामगोपाल शास्त्राजी :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में ठेका प्रणाली को समाप्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) से (ग) : मामला विचाराधीन है।

फिल्म सेंसर बोर्ड

2878. श्री श्रीम प्रकाशश्यामी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 27 मार्च, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड को सरकार द्वारा सुभाये गये सिद्धांतों का व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोई ऐसा चलचित्र है जो उक्त बोर्ड द्वारा पास नहीं किया गया था परन्तु बाद में केन्द्रीय सरकार ने उसे दिखाये जाने की अनुमति दी अथवा कोई ऐसा चलचित्र है जो उक्त बोर्ड द्वारा पास कर दिया गया था परन्तु उसे बाद में सरकार ने दिखाये जाने की अनुमति नहीं दी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे चलचित्रों के नाम क्या-क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री श्री (इ० कु० गुजराल) :
(क) भारत के राजपत्र जी० एस० आर० 168, तारीख 6 फरवरी, 1960 में प्रकाशित केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या LT 327/69] इन निर्देशों में सेंसर बोर्ड को यह बताया गया है कि उसे सांख्यिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए।

(ख) और (ग). 1965-66, 1966-67 और